THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF POWER (DR. S. VENUGOPALACHARI): (a) to (e) Overseas Economic Cooperation Fund (OECF) of Japan have appriaised/are appraising the following power projects for a loan package for 1996-97:—

i. Dhauliganga Transmission System (Uttar Pradesh) & Jalandhar (Punjab)—Hamirpur (Himachal Pradesh) Transmission System of Powergrid Corporation of India Limited.

ii. Strengthening of Transmission System of West Bengal.

iii. Renovation & Modernisation Plan of Umiam Stage I Power Station (36 MW), Meghalaya.

iv. Turial Hydro-Electric Project (60 MW), Mizoram.

v. Simhadri Thermal Power Project Stage I (1000 MW), Andhra Pradesh.

vi. Anpara 'C Thermal Power Station Construction Project (1000 MW), Uttar Pradesh.

The final decision about extending loans for these projects would be known only at the time of the meeting of the India Development Forum to be held in September, 1996 in Tokyo (Japan).

Guidelines for the Preparation of the Ninth Plan

1819. DR. D. VENKATESHWAR RAO: Will the Minister of PLANNING AND PROGRAMME IMPLEMENTATION be pleased to state:

(a) whether Government have formulated any guidelines in the preparation of the Ninth Five Year Plan;

(b) if so, whether the Planning Commission has prepared a draft model after going through reports of various working groups and steering committees;

(c) if so, the main features of the same; and

(d) by when a final decision is likely to be taken?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF PLANNING AND PROGRAMME IMPLEMENTATION (SHRI YOGINDER K. ALAGH): (a) and (b) No, Sir,

(c) and (d) The guidelines for the Ninth Plan will form part of the Approach Paper of the Ninth Five year Plan, which is under process now and is expected to be completed in four months time.

कश्मीर में मारे गये बिहारी मजदूर

1820. श्री रामदेव भंडारी: क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) कश्मीर के कुपवाड़ा जिले में हाल ही में मारे गये ग्यारह बिहारी मजदूरों तथा अन्य घायल मजदूरों के संबंध में ब्यौरा क्या है;

(ख) सरकार कश्मीर में कार्यरत अन्य राज्यों के मजदूरों की जान-माल की रक्षा हेतु क्या व्यवस्था कर रही है; और

(ग) सरकार मृतक तथा घायल मजदूरों के परिवार वालों के लिये मुआवजा, नौकरी आदि के रूप में क्या-क्या सुविधायें दे रही है?

कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस॰ आर॰ बालासुब्रमण्यन): (क) जम्मू और कश्मीर सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गयी सूचना के अनुसार 6-7 जुलाई 1996 के बीच की रात को कुछ अज्ञात उग्रवादियों ने 18 मजदूरों का अपहरण कर लिया, जो गांव उत्तर-टोला, जिला-बलिया, उत्तर प्रदेश के रहने वाले थे और उन्हें जम्मू और कश्मीर में कुपवाड़ा जिले में, हन्डवाड़ा के नजदीक, गांव घोटीपोरा में ईंट के भट्टे में काम पर लगाया गया था।

इनमें से 11 व्यक्तियों की हत्या कर दी गयी, 5 जख्मी हुए और दो बच कर भाग निकले। वरिष्ठ अधिकारी घटनास्थल पर गए और एक मामला दर्ज किया गया, जिसकी जांच पड़ताल की जा रही है।

(ख) सुरक्षा प्रबन्धों को सुदृढ़ करने के लिए सतत प्रयास करने और आतंकवादियों की गतिविधियों को रोकने के लिए सतत अभियान चलाने के अलावा, जम्मू और कश्मीर सरकार ने सभी संबंधियों को सलाह दी है कि काम करने के लिए राज्य के बाहर से आने वाले ऐसे व्यक्तियों को भीतरी क्षेत्रों, जो इस प्रकार के आसान लक्ष्यों के प्रति लक्षित आतंकवादी गतिविधियों के लिए संवेदनशील हो सकते हैं, में जाने से बचना चाहिए। मजदूरों के रूप में कार्य करने के लिए बाहर से आने वाले व्यक्तियों को भी सलाह दी गयी है कि वे अपने ठहरने के स्थान इत्यादि के बारे में ब्यौरे नजदीक के पुलिस स्टेशन को दें, ताकि आवश्यक सतर्कता और सुरक्षा उपाय किए जा सके।

(ग) कुपवाड़ा के जिला मजिस्ट्रेट ने प्रत्येक मृतक के नजदीकी रिश्तेदार को 1 लाख रु० की दर से अनुग्रहपूर्वक राहत स्वीकृत की है, जिसे बलिया के जिला मजिस्ट्रेट के माध्यम से वितरित किया जा रहा है।

Closing Down of Power Plants

1821. MAULANA OBAIDULLAH KHAN AZMI: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) the number of Power Plants which had to close down during the last year due to non-supply of required quantity of coal; and

(b) the corrective steps being taken in this regard?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF POWER (DR. S. VENUGOPALACHARI): (a) and (b) No power station was closed down during the last year on account of non-supply of required quantity of coal. However, a few power stations had to reduce generation by shutting of units due to less supply of coal. The coal availability in the Country is being augmented through higher production and greater coordination in its movement by Railways etc.

विज्ञान और प्रौद्योगिकी पर व्यय

1822. श्री इकबाल सिंह: क्या विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार ने आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान विज्ञान और प्रोद्योगिकी हेतु कितनी धनराशि का आवंटन किया है;

(ख) अब तक व्यय की गई धनराशि का ब्यौरा क्या है; और

(ग) देश में अनुसंधान और विकास पर व्यय, जो सकल राष्ट्रीय उत्पाद का 0.83 प्रतिशत है, उसे बढ़ाकर 2 प्रतिशत करने के संबंध में सरकार द्वारा क्या आवश्यक तथा ठोस कदम उठाये जा रहे हैं?

योजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रोद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र के०अलघ): (क) आठवीं योजना परिव्यय के कुल 4119.00 करोड़ रुपये की तुलना में, विज्ञान और प्रोद्योगिकी एजेंसियों/विभागों के लिए वास्तविक योजना परिव्यय 6266.00 करोड़ रुपये है।

(ख) वर्ष 1992-96 के दौरान खर्च की गई राशि का ब्यौरा इस प्रकार है:—

रुपये करोड़ में

1.	परमाणु ऊर्जा विभाग	481.04
2.	महासागर विकास विभाग	154.50
3.	विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग	780.18
4.	वैज्ञानिक और औद्योगिकी अनुसंधान विभाग	600.93
5.	अंतरिक्ष विभाग	2265.71
6.	जैव प्रोद्योगिकी विभाग	313.78
7.	फौरेंसिक सायंस और पुलिस वायर लैस	5.95

(ग) सरकार इस विचार से अवगत है कि अनुसंधान तथा विकास पर खर्च को कुल राष्ट्रीय उत्पाद के 2 प्रतिशत तक बढ़ाए जाने की आवश्यकता है।